भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3210** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पत्तन प्रचालनों का डिजिटलीकरण

† 3210. श्री तेजस्वी सूर्या :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना के अंतर्गत पत्तन प्रचालनों के डिजिटलीकरण हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्तन प्रचालनों के डिजिटलीकरण से देश में पत्तन कार्यकुशलता पर अनुमानत: क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): भारत सरकार समुद्री क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता और व्यापार की सुगमता के लिए पत्तन प्रचालनों को डिजिटल बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। पत्तन प्रचालनों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा, सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक "पत्तन आधुनिकीकरण" स्तंभ का एक हिस्सा है।

दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए, सरकार ने एनएलपी मरीन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य आईटी का उपयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स समुदाय के सभी हितधारकों को जोड़ने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। सागर सेतु (एनएलपी-मरीन) में मैरीन सिंगल विंडो (एमएसडब्लू) और वाणिज्यिक समुद्री विभाग (एमएमडी) मॉड्यूल लॉन्च किए गए हैं। एमएसडब्ल्यू मॉड्यूल एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे समुद्री संबंधित सूचनाओं और दस्तावेजों के आदान-प्रदान में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कुशल आंकड़ा प्रस्तुति के लिए सामंजस्य और मानकीकरण पर बल दिया गया है।

सितंबर, 2024 में गोवा में आयोजित 20वीं एमएसडीसी बैठक में मंत्रालय ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म पर पत्तनों में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएसपीसी) एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, कार्यकुशलता में सुधार लाने और हितधारकों के लिए लागत कम करने के लिए विकसित की गई है।

(ग): पत्तन प्रचालनों के डिजिटलीकरण से पत्तन की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, लागत में बचत होगी, टर्न अराउंड समय में कमी आएगी और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार होगा। डिजिटल तकनीकों से न केवल उनकी प्रचालन दक्षता में सुधार होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुगमता आएगी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

*****